Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 23-2015] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 9, 2015 (JYAISTHA 19, 1937 SAKA)

General Review

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2010–2011 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 28 मई, 2015

क्रमांक 30/4-2011 (तम) आंकड़ा

प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप से कई गुणा विस्तार हुआ है। विस्तार का यह ग्राफ वर्ष 2010–11 में भी बढ़ता रहा । राज्य में शिक्षा की संस्थात्मक क्षमता की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ । राज्य उच्च तकनीक अपनाकर उत्कृष्ट तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहा है ।

वर्ष 2010–2011 में उच्चतर शिक्षा पर कुल 75371.97 लाख रुपये की राशि व्यय की गई, इसमें योजनेत्तर पक्ष पर 56976.79 लाख रुपये, योजना पक्ष पर 18395.18 लाख रुपये तथा केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों पर 29.99 लाख रुपये व्यय हुए। राज्य में चार विश्वविद्यालयों महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा तथा भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत कार्यरत हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र जीन्द में तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र मीरपुर में स्थापित किया गया।

वर्ष 2010–2011 में 174 महाविद्यालयों एवं 4 विश्वविद्यालयों में 4,44,050 छात्र संख्या थी तथा लगभग 5341 सहायक प्राध्यापकों/सह प्राध्यापकों/प्रोफेसरों ने शिक्षा प्रदान की ।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। संकलित स्टाइफण्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 26,221 विद्यार्थियों को 31,95,12,500/– रुपये दिये गये । मैरिट में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेघावी छात्रों को 1377 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिस पर 53,91,000/– रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त राज्य मैरिट छात्रवृत्ति के तहत 1192 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन छात्रवृत्तियों पर 48,92,400/– रुपये व्यय किए गए।

वर्ष 2010.11 में ''कमायें जब आप शिक्षा पायें'' योजना के अन्तर्गत 120.00 लाख रुपये का प्रावधान करवाया गया और लगभग 6000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में सेमिनार/रिफ्रेशर कोर्स तथा आरियन्टेशन कोर्स आयोजित किए गए जोकि अध्यापक एवं सहायक स्टाफ की उन्नति के लिए लाभदायक होंगे । वर्ष 2010–11 में राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार कक्ष स्थापित करने के लिए 50.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान करवाया गया।

राज्य में विद्यार्थी कैडेट्स/स्वयं सेवकों के चहुंमुखी विकास के लिए एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 कार्यक्रम चल रहे हैं। इन एन0सी0सी0 कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए 8,38,09,000/– रुपये की राशि प्रदान की गई । एन0एस0एस0 सेवकों की पंजीकृत संख्या 1,05,148 थी तथा एन0एस0एस0 कार्यक्रम के लिए 3,25,81,000/– रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

वर्ष 2010–11 में आम जनता में पढ़ने की आदत डालने के लिए एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय तथा 6 उपमण्डल पुस्तकालय राज्य में कार्य कर रहे थे। रिपोर्टाधीन अवधि में सभी राजकीय महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालयों की सेवायें सुदृढ़ करने हेतू 150.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई और 105.00 लाख रुपये की राशि 19 जिला पुस्तकालयों तथा 6 उपमण्डल पुस्तकालयों को प्रदान की गई।

वर्ष 2010–2011 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री रही जबकि श्री एस0 एस0 प्रसाद वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के पद पर रहे और श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, आई0ए0एस0 ने उच्चतर शिक्षा आयुक्त के पद पर कार्य किया।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मई, 2015

Review of the Annual Administrative Report of the Higher Education Department, Haryana for the year 2010-11

The 28th May, 2015

No. 30/4-2011 Stat.

The Haryana State has witnessed a many fold increase in the field of Higher Education quantitatively as well as qualitatively since 1st November, 1966. The graph of expansion of Higher Education kept moving upward during 2010-11 also. The institutional capacity of the State has increased, which has facilitated expansion of education especially in rural areas. The State Higher Education has become hi-tech and is reaping the benefits of advanced technology.

During 2010-11, a total amount of Rs. 75,371.97 lakh was spent on Higher Education, Rs. 56,976.79 lakh on non-plan side, Rs. 18,395.18 lakh on plan side and 29.99 lakh was spent on centrally sponsored schemes. Four State Universities, namely M.D.U. Rohtak, K.U. Kurukshetra, C.D.L.U, Sirsa and B.P.S M.V. Khanpur Kalan, Sonepat have been working in the State. Field office of Maharishi Dayanand University was functional at Meerpur and field offices of Kurukshetra University, Kurukshetra at Jind.

During 2010-11, 174 Colleges and 4 State Universities have been imparting education to about 4,44,050 students and these were served by 5341 Assistant Professors/ Associate Professor/ Professors.

Stipends were provided to students belonging to S.C. category and weaker sections of the society. Under a Consolidated Stipends Scheme, students belonging to S.C. Category were given Rs. 31,95,12,500/- amongst 26,221 students. An amount of Rs. 53,91,000/- was distributed amongst 1377 excellent students getting first, second and third position in merit under Meritorious Incentive Scheme in State Government Colleges. In addition to it, an amount of Rs.48,92,400/- was spent amongst 1192 students under the State Merit Scholarship.

During the reporting period year 2010-11,a grant of Rs. 120.00 lakh was utilized for the scheme 'Earn While You Learn' in Government Colleges and about 6000 students were benefited under this scheme.

Under the Human Resource Development Scheme, seminars, refresher courses and orientation courses were sponsored by the department in different colleges whereas an amount of Rs. 50.00 lakh was spent on placement cells in the Government Colleges.

N.C.C. and N.S.S. programmes are being run in the State with the objective of bringing all round development of student. An amount of Rs. 8,38,09,000/- lacs was spent for training and other expenses of N.C.C. cadets. The enrolled strength of N.S.S. volunteers was 1,05,148 and a total budget of Rs. 3,25,81,000/- was provided for conducting N.S.S. programmes.

For disseminating knowledge and inculcating the reading habit in general public, 01 Central State Library, 19 District Libraries, 6 Sub Divisional Libraries were functioning in the State during 2010-11. During this period

Rs. 150.00 lakh was allocated for all Government Colleges libraries and Rs.105.00 lakh was allotted for 19 District Libraries and 6 Sub Divisional Libraries to augment the libraries.

During 2010-11 Smt. Geeta Bhukkal was the Education Minister while Sh. S.S. Prasad, IAS was the Financial Commissioner and Principal Secretary Higher Education and Smt. Dheera Khandelwal, IAS held the office of Higher Education Commissioner.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

Chandigarh :
The 6th May, 2015

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2011–2012 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 28 मई, 2015

क्रमांक 30/5-2012 तम (आंकड़ा)

प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप से कई गुणा विस्तार हुआ है। विस्तार का यह ग्राफ वर्ष 2011–12 में भी बढ़ता रहा । राज्य में शिक्षा की संस्थात्मक क्षमता की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ । राज्य उच्च तकनीक अपना कर उत्कृष्ट तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहा है ।

वर्ष 2011–2012 में उच्चतर शिक्षा पर कुल 82984.01 लाख रुपये की राशि व्यय की गई, इसमें योजनेत्तर पक्ष पर 64006.75 लाख रुपये, योजना पक्ष पर 18945.20 लाख रुपये तथा केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों पर 32.06 लाख रुपये व्यय हुए। राज्य में चार राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा तथा भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय जाँटपाली, महेन्द्रगढ़ कार्यरत हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र जीन्द में तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र मीरपुर में स्थापित किया गया।

वर्ष 2011–2012 में 176 महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों में 5,10,632 छात्र संख्या थी तथा लगभग 5316 सहायक प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/प्रोफेसरों ने शिक्षा प्रदान की ।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। संकलित स्टाइफण्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 29938 विद्यार्थियों को 27,65,50,000/– रुपये दिये गये । मैरिट में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 2300 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिस पर 52,75,000/– रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त राज्य मैरिट छात्रवृत्ति के तहत 1207 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन छात्रवृत्तियों पर 50,41,800/– रुपये व्यय किए गए।

वर्ष 2011-12 में ''कमायें जब आप शिक्षा पायें'' योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों 130.00 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया और लगभग 6000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में सैमिनार/रिफ्रेशर कोर्स, तथा आरियन्टेशन कोर्स आयोजित किए गए जोकि अध्यापक एवं सहायक स्टाफ की उन्नति के लिए लाभदायक होंगे। राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार कक्ष स्थापित करने के लिए वर्ष 2011–12 में 55.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया।

राज्य में विद्यार्थी कैडेट्स/स्वयं सेवकों के चहुंमुखी विकास के लिए एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्ष 2011–12 नान–प्लान पक्ष पर भिन्न–भिन्न एन.सी.सी यूनिटों हेतु 8,14,30,000/– रुपये की राशि एवं प्लान पक्ष पर तीसरी कन्या बटालियन हिसार हेतु 15,00,000/– रुपये की राशि अलॉट की गई। एन.एस.एस. कैम्प में 105148 स्वयंसेवकों/सेविकाओं ने भाग लिया इसके लिए 4,99,23,000/– रुपये की राशि अलॉट की गई।

वर्ष 2011–12 में आम जनता में पढ़ने की आदत डालने के लिए एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय तथा 6 उपमण्डल पुस्तकालय राज्य में कार्य कर रहे थे। रिपोर्टाधीन अवधि में सभी राजकीय महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालयों की सेवायें सुदृढ़ करने हेतू 200.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2011–12 में 25 राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में इलैक्ट्रानिक लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी है।

वर्ष 2011–2012 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री रही, जिनके योग्य नेतृत्व में निदेशालय ने शिक्षा को एक नई गति प्रदान की। श्री एस0 एस0 प्रसाद वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के पद पर रहे। श्री बलबीर सिंह मलिक, आई0ए0एस0 ने महानिदेशक उच्चतर शिक्षा के पद पर कार्य किया।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मई, 2015

Review of the Annual Administrative Report of the Higher Education Department, Haryana for the year 2011-12

The 28th May, 2015

No. 30/5-2012 Stat.

The Haryana State has witnessed a many fold increase in the field of Higher Education quantitatively as well as qualitatively since 1st November, 1966. The graph of expansion of Higher Education kept moving upward during 2011-12 also. The institutional capacity of the State increased, which has facilitated expansion of education especially in rural areas. The State Higher Education has become hi-tech and is reaping the benefit of advanced technology.

During 2011-12, a total amount of Rs. 82984.01 lakh was spent on Higher Education, Rs. 64006.75 lakh on non-plan side, Rs. 18945.20 lakh on plan side and 32.06 lakh was spent on centrally sponsored schemes. Four State Universities, namely M.D.U. Rohtak, K.U. Kurukshetra, C.D.L.U, Sirsa and B.P.S.M.V. Khanpur Kalan, Sonepat and One Central University Jantpali, Mahendergarh 9 Private Universities have been functioning in the State. Field office of Maharishi Dayanand University was functional in Meerpur and field office of Kurukshetra University, Kurukshetra at Jind.

During 2011-12, 176 Colleges, 5 State Universities and 9 private universities have been imparting education to about 5,10,632 students and these were served by 5316 Assistant Professors/ Associate Professors/ Professors.

Stipends were provided to students belonging to S.C. category and weaker sections of the society. Under a Consolidated Stipends Scheme, students belonging to S.C. category were given Rs. 27,65,50,000/- amongst 29938 students. An amount of Rs. 52,75,000/- was distributed amongst 2300 excellent students getting first, second and third position in merit under Meritorious Incentive Scheme in State Government Colleges. In addition to it an amount of Rs.50,41,800/- was spent amongst 1207 students under the State Merit Scholarship Scheme.

During the reporting period year 2011-12, a grant of Rs. 130.00 lakh was disbursed for the scheme 'Earn While You Learn' Scheme in Government Colleges and about 6000 students were benefited under this scheme.

Under Human Resource Development Scheme seminars, refresher courses and orientation courses were sponsored by the department in different colleges, whereas an amount of Rs. 55.00 lakh was spent on placement cells in the Government Colleges of the State.

N.C.C. and N.S.S. programme are being run in the State with the aim of bringing all round development of students. An amount of Rs. 8,14,30,000/- lakh (Non Plan) was spent on training and other expenses of N.C.C. cadets and an amount of Rs. 15,00,000/- (Plan) was allotted for planning the 3rd girls battalion, Hisar. The enrolled strength of N.S.S. volunteers was 1,05,148 and a total budget of Rs. 4,99,23,000/- was provided for conducting N.S.S. programmes.

For disseminating knowledge and inculcating the reading habit in general public, 01 Central State Library, 19 District Libraries, 6 Sub Divisional Libraries were functioning in the State during 2011-12.

During this period Rs. 200.00 lakh was allocated for all Government Colleges libraries whereas Electronic Libraries were established in 25 Government Colleges of excellence.

During 2011-12 Smt. Geeta Bhukkal, Education Minister while Sh. S.S. Prasad, was Financial Commissioner and Principal Secretary, Higher Education Department and Sh. Balbir Singh Malik, IAS held the office of Higher Education Commissioner.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

Chandigarh :
The 6th May, 2015

उच्चतर शिक्षा विभाग की वर्ष 2012–2013 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 28 मई, 2015

क्रमांक 30/5-2013 तम 5

प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप से कई गुणा विस्तार हुआ है। विस्तार का यह ग्राफ वर्ष 2012–13 में भी बढ़ता रहा । राज्य में शिक्षा की संस्थात्मक क्षमता की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ । राज्य उच्च तकनीक अपनाकर उत्कृष्ट तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहा है ।

वर्ष 2012–2013 में उच्चतर शिक्षा पर कुल 93173.93 लाख रु0 की राशि व्यय की गई, इसमें योजनेत्तर पक्ष पर 65386.36 लाख रु0, योजना पक्ष पर 27742.66 लाख रुपये तथा केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों पर 44.91 लाख रु0 व्यय हुए । राज्य में पांच विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा तथा भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत और केन्द्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली, महेन्द्रगढ़ उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र जीन्द में तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र मीरपुर में कार्यरत है।

वर्ष 2012–2013 में 185 महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों में 4,74,584 छात्र संख्या थी तथा लगभग 5506 सहायक प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों ने शिक्षा प्रदान की ।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। संकलित स्टाइफण्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 35218 विद्यार्थियों को 45,00,90,471/– रुपये दिये गये । मैरिट में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 14 छात्रवृत्तियां हेतु 6,50,000/– रुपये वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य मैरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत 1266 छात्रवृत्तियां दी गई तथा इन छात्रवृत्तियों पर 52,00,400/– रुपये व्यय किए गए।

वर्ष 2012–13 में "कमायें जब आप शिक्षा पायें" योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को 120.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई और लगभग 5000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में सेमिनार, वर्कशाप, रिफ्रेशर कोर्स तथा आरियन्टेशन कोर्स आयोजित किए गए जोकि अध्यापक एवं सहायक स्टाफ की उन्नति के लिए लाभदायक होंगे । वर्ष 2012–13 में राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार सहायता–कक्ष स्थापित करने के लिए 40.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान करवाया गया है ।

राज्य में विद्यार्थी कैडेट्स/स्वयं सेवकों के चहुंमुखी विकास के लिए एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 कार्यक्रम चल रहे हैं। इन एन0सी0सी0 कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए 9,63,00,000/– रुपये की राशि प्रदान की गई । एन0एस0एस0 सेवकों की पंजीकृत संख्या 1,05,148 थी तथा एन0एस0एस0 कार्यक्रम के लिए 4,99,22,500/– रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

वर्ष 2012–13 में आम जनता में पढ़ने की आदत डालने के लिए 01 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय तथा 7 उपमण्डल पुस्तकालय राज्य में कार्य कर रहे थे। रिपोर्टाधीन अवधि में सभी राजकीय महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालयों की सेवायें सुदृढ़ करने हेतू 150.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई और 66.00 लाख रुपये की राशि का 19 जिला पुस्तकालयों तथा 7 उपमण्डल पुस्तकालयों को प्रदान की गई।

वर्ष 2012–2013 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री रहीं जबकि श्री एस0 एस0 प्रसाद वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के पद पर रहे और श्री बलबीर सिंह मलिक, आई0ए0एस0 तथा उसके उपरान्त तक श्री अंकुर गुप्ता, आई0ए0एस0 ने महानिदेशक उच्चतर शिक्षा के पद पर कार्य किया।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 मार्च, 2015

Review of the Annual Administrative Report of the Higher Education Department, Haryana for the year 2012-13

The 28th May, 2015

No. 30/5-2013 Co.(5)

The Haryana State has witnessed a many fold increase in the field of Higher Education quantitatively as well as qualitatively since 1st November, 1966. The graph of expansion of Higher Education kept moving upward during 2012-13 also. The institutional capacity of the State increased, which has facilitated expansion of education especially in rural areas. The State Higher Education has become hi-tech and is reaping the benefit of advanced technology.

During 2012-13, a total amount of Rs. 93173.93 lakh was spent on Higher Education Rs. 65386.36 lakh on non-plan side, Rs. 27742.66 lakh on plan side and 44.91 lakh was spent on centrally sponsored schemes. Five State Universities namely M.D.U. Rohtak, K.U. Kurukshetra, C.D.L.U. Sirsa and B.P.S.M.V. Khanpur Kalan, Sonepat and Central University, Jant Pali, Mahendergarh have been working in the State. Field office of Maharishi Dayanand University was functional at Meerpur and field office of Kurukshetra University, Kurukshetra was working at Jind.

During 2012-13, 185 Colleges, 1 Central University and 4 State Universities have been imparting education to about 4,74,584 students and these were served by 5506 Assistant Professors/ Associate Professors/ Professors.

Stipends were provided to students belonging to S.C. category and other weaker sections of the society. Under a Consolidated Stipends Scheme, students belonging to S.C. category were given Rs. 45,00,90,471/- amongst 35218 students. An amount of Rs. 6,50,000/- was distributed amongst 14 excellent students getting first, second and third position in merit under scholarship scheme in State Government Colleges. In addition to it an amount of Rs. 52,00,400/- was spent amongst 1266 students under the State Merit Scholarship Scheme.

During reporting period year 2012-13, grant of Rs. 120.00 lakh was utilized for the scheme 'Earn While You Learn' in Government Colleges and 5000 students were benefited under this scheme.

Under the Human Resource Development Scheme seminars, workshop, refresher courses and orientation courses were sponsored by the department in different colleges whereas an amount of Rs. 40.00 lakh was spent on placement cells in the Government Colleges of the State.

N.C.C. and N.S.S. programmes are being run in the State with the aim of bringing all round development of N.C.C. cadets/ N.S.S. volunteers. An amount of Rs. 9,63,00,000/- lakh was spent on training and other expenses of N.C.C. cadets. The enrolled strength of N.S.S. volunteers was 1,05,148 and a total budget of Rs. 4,99,22,500/- was provided for conducting N.S.S. programmes.

For disseminating knowledge and inculcating the reading habit in general public, 01 Central State Library, 19 District Libraries, 7 Sub Divisional Libraries were functioning in the State during 2012-13. During this period Rs. 150.00 lakh was allocated for all Government College libraries and Rs.66.00 lakh was allotted for 19 District Libraries and 7 Sub Divisional Libraries to augment the libraries.

During 2012-13, Smt. Geeta Bhukkal was the Education Minister while Sh. S.S. Prasad, IAS was the Financial Commissioner & Principal Secretary, Higher Education and Sh. Balbir Singh Malik, IAS and Sh. Ankur Gupta, IAS remained posted as Director General Higher Education, Government of Haryana.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

Chandigarh :
The 2nd March, 2015.

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 2013–2014 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 28 मई, 2015

क्रमांक 30/3–2014 आंकड़ा

प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप में कई गुणा विस्तार हुआ है। विस्तार का यह ग्राफ वर्ष 2013–14 में भी बढ़ता रहा। राज्य में शिक्षा की संस्थात्मक क्षमता की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। राज्य उच्च तकनीक अपना कर उत्कृष्ट तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहा है ।

वर्ष 2013–2014, में उच्चतर शिक्षा पर कुल 109821.64/–लाख रुपये की राशि व्यय की गई, इसमें योजनेत्तर पक्ष पर 68547.69/– लाख रुपये, योजना पक्ष पर 31623.24/– लाख रुपये तथा केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों पर 14.96/– लाख रुपये व्यय हुए। राज्य में पांच विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, सोनीपत, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, रेवाड़ी और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय जॉटपाली, महेन्द्रगढ़ उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र जीन्द में चल रहा है।

वर्ष 2013–2014 में 192 महाविद्यालयों, 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं 5 विश्वविद्यालयों में लगभग 4,99,327 छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा इनमें 5803 सहायक प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों ने शिक्षा प्रदान की ।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। संकलित स्टाइफण्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 37328 विद्यार्थियों को 42,00,00,000/– रुपये दिये गये । राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैरिट में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 1842 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जिस पर 54,02,000/– रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त राज्य मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 1017 छात्रों पर 43,00,000/– रुपये व्यय किए गए।

वर्ष 2013.14 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ''कमायें जब आप शिक्षा पायें'' योजना के अन्तर्गत सभी राजकीय महाविद्यालयों को 117.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई एवं इस योजना के तहत लगभग 7500 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स कार्यशालाएं तथा अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार कक्षों हेतु 60.00 लाख रु0 की राशि व्यय की गई।

राज्य में विद्यार्थी कैडेट्स/स्वयं सेवकों के चहुंमुखी विकास लाने के उद्देश्य से एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 कार्यक्रम चलाए गए हैं । इन एन0सी0सी0 कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए एवं उनके अन्य खर्चों 12,99,95,000/– लाख रु0 की राशि खर्च की गई । एन0एस0एस0 सेवकों की पंजीकृत संख्या 1,05,148 थी तथा एन0एस0एस0 कार्यक्रमों के लिए कुल 4,99,23,000/– रु0 की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 2013–14 में आम जनता के ज्ञान वर्धन हेतु एवं पढ़ने की आदत डालने के लिए एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय तथा 7 उपमण्डल पुस्तकालय राज्य में कार्य कर रहे थे। इस अवधि के दौरान 95 राजकीय महाविद्यालयों को 250.00 लाख रु0 की राशि एवं 19 जिला पुस्तकालयों तथा 7 उपमण्डल पुस्तकालयों को 150.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

वर्ष 2013–2014 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री के योग्य निर्देशन में निदेशालय ने शिक्षा को एक नई गति प्रदान की। श्री एस0 एस0 प्रसाद, आई0ए0एस0 अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा के पद पर रहे। श्री अंकुर गुप्ता, आई0ए0एस0 ने महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा के पद पर कार्य किया।

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मई, 2015

Review of the Annual Administrative Report of the Higher Education Department, Haryana for the year 2013-14

The 28th May, 2015

No. 30/3-2014 Stat.

The Haryana State has witnessed many fold increase in the field of Higher Education quantitatively as well as qualitatively since 1st November, 1966. The graph of expansion of Higher Education kept moving upward during 2013-14 also. The institutional capacity of the State increased, which has facilitated expansion of education especially in rural areas. The State Higher Education has become hi-tech and is reaping the benefits of advanced technology.

During 2013-14, a total amount of Rs. 109821.64 lakh was spent on Higher Education, Rs. 68,547.69 lakh on non-plan side, Rs. 31,623.24 lakh on plan side and 14.96 lakh was spent on centrally sponsored schemes. Five State Universities namely M.D.U. Rohtak, K.U. Kurukshetra, C.D.L.U. Sirsa, B.P.S M.V. Khanpur Kalan, Sonepat, Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari and One Central University, Jantpali, Mahendergarh respectively have been providing higher education in the State while P.G.R.C. of Kurukshetra University, Kurukshetra is doing so at Jind.

During 2013-14, 192 Colleges, 1 Central University and 5 State Universities imparted education to 4,99,327 students and these were served by 5803 Assistant Professor/ Associate Professors/ Professors.

Stipends were provided to students belonging to S.C. category and weaker sections of the society. Under the consolidated Stipends scheme 37,238 students belonging to S.C. category were given Rs. 42,00,00,000/-. An amount of Rs. 54,02,000/- was distributed amongst 1842 excellent students who obtained first, second and third positions in merit under scholarship scheme in State Government Colleges. In addition to it an amount of Rs. 43,00,000/- was spent amongst 1017 students under the State Merit Scholarship.

During reporting period i.e. 2013-14 a grant of Rs. 117.00 lakh was utilized for the scheme 'Earn while you learn' and was also distributed to all Government Colleges and 7500 students benefited under this scheme.

Under Human Resource Development Scheme, seminars, refresher courses and orientation courses were sponsored by the department in different colleges. An amount of Rs. 60.00 lakh was spent on placement cells in the Government Colleges of the State.

N.C.C. and N.S.S. programmes are being run in the State with the aim of bringing all round development of student cadets/volunteers. An amount of Rs. 12,99,95,000/- lakh was spent on training and other expenses of N.C.C. cadets. The enrolled strength of N.S.S. volunteers was 1,05,148 and a total budget of Rs. 4,99,23,000/- was provided for conducting N.S.S. programmes.

For disseminating knowledge and inculcating the reading habit in general public, 01 Central State Library, 19 District Libraries, 7 Sub Divisional Libraries were functioning in the State during 2013-14. During this period Rs. 250.00 lakh was allocated for 95 Government Colleges and Rs.150.00 lakh was allotted for 19 District Libraries and 7 Sub Divisional Libraries to augment the libraries.

Smt. Geeta Bhukkal was the Education Minister during 2013-14. Sh. S.S. Prasad, IAS held the office of Additional Chief Secretary to Government of Haryana Higher Education Department. During the reporting period Sh. Ankur Gupta, IAS held the office of Director General Higher Education, Haryana.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

Chandigarh :
The 6th May, 2015

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2012–2013 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 1 जून, 2015

क्रमांक 529-SW(1)2015

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वर्ष 2012–2013 में स्टेट प्लान (14290.00 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित (10785.20 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (1697.50 लाख रुपये) तथा नान प्लान (10252.85 लाख रुपये) योजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि 37025.55 लाख रुपये थी। उपरोक्त निर्धारित राशि में से 33739.25 लाख रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य प्लान (13702.12 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रयोजक प्लान (4141.75 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (1697.50 लाख रुपये) तथा नान प्लान स्कीम (14197.88 लाख रुपये) में खर्च की गई।

2. स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रयोजक, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान स्कीमों का सारांश इस प्रकार है :–

(क) राज्य प्लान स्कीमें

(1) "अनुसूचित जातियों को मकान बनाने/मरम्मत हेतु डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत 2005.40 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 4254 लाभपात्रों को प्रदान की गई ।

(2) टपरीवास एवं विमुक्त जातियों के लिए मकान निर्माण/मरम्मत हेतु डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत 198.00 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 412 लाभपात्रों को प्रदान की गई।

(3) हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 100.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 131.55 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

(4) "अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 168.57 लाख रुपये की राशि 2000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने पर खर्च की गई।

(5) इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 8195.88 लाख रुपये की राशि 32676 लाभपात्रों को वर्ष 2012–13 में प्रदान की गई।

(6) सिविल सर्विसिज तथा उच्च प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को प्राईवेट अच्छी साख वाले संस्थाओं से प्रशिक्षण कोचिंग प्रदान करने हेतु वर्ष 2012–2013 में 32.05 लाख रुपये की राशि 880 छात्रों पर व्यय की गई ।

(7) वर्ष 2012–13 में 'हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम' को प्रशासकीय खर्चे जुटाने हेतु 434.57 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है ।

(8) वर्ष 2012–13 में डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 1799.70 लाख रुपये की राशि 22686 (18080 अनुसूचित जाति एवं 4606 पिछड़ा वर्ग) छात्रों को प्रदान की गई ।

(9) सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत 23.65 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012–13 में खर्च की गई ।

(10) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल स्कीम पर 43.87 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012–13 में 180 युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु खर्च की गई।

(11) अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 2.86 लाख रुपये की राशि 32 अनुसूचित जाति की लड़कियों को प्रदान की गई है।

(12) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 28 संस्थाओं/समितियों को वर्ष 2012–13 में 50.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(1) अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों हेतु तीन होस्टलों के निर्माण पर वर्ष 2012–13 में 210.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(2) भारत सरकार की "पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 14467.84 लाख रुपये (11251.72 लाख नान प्लान तथा 3216.12 लाख केन्द्रीय हिस्सा) 83377 अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई।

(3) भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अन्तर्गत् वर्ष 2012–13 में 510.51 लाख रुपये की राशि 53191 पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई ।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की मैरिट अपग्रेडशन स्कीम पर वर्ष 2012–13 में 16.95 लाख रुपये की राशि 64 छात्रों पर खर्च की गई है।

(5) ''पी.सी.आर. एक्ट 1955'' तथा ''अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989'' के परिपालन हेतु मशीनरी के अन्तर्गत स्कीमें :–

(क) कानूनी सहायता स्कीम

वर्ष 2012–13 में कानूनी सहायता स्कीम के अन्तर्गत 3.48 लाख रुपये (1.74 लाख रुपये राज्य प्लान व 1.74 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 64 लोगों को प्रदान की गई।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 211 नव विवाहित जोड़ों को 105.50 लाख रुपये (52.75 लाख रुपये प्लान तथा 52.75 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई ।

(ग) पंचायतों को पुरस्कार, स्कीमों का प्रचार तथा छुआछूत दूर करने हेतु डिबेटस व सेमिनार

इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 74.10 लाख रुपये (37.05 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 37.05 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि खर्च की गई। जिसमें से 40.50 लाख रुपये (20.25 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 20.25 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 81 पंचायतों को पुरस्कार के रूप में तथा 30.58 लाख रुपये (15.29 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 15.29 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। 3.02 लाख रुपये (1.51 लाख रुपये स्टेट प्लान व 1.51 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 48 डिबेटस एवं सेमिनार पर खर्च की गई।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989)के अन्तर्गत अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 193.26 लाख रुपये (96.63 लाख रुपये प्लान तथा 96.63 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 212 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान की गई।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम

वर्ष 2012–13 में विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत 1197.50 लाख रुपये की राशि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को भिन्न भिन्न आय उपार्जन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु प्रदान की गई, हरियाणा उर्जा विकास एजैन्सी को 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 500 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतु 176.00 लाख रुपये की राशि अलाट की गई जो कि उन द्वारा अपने लेखा शीर्ष से उपलब्ध करवाई गई।

(घ) नान प्लान स्कीमें

(1) अस्वच्छ कार्यों अर्थात् शुष्क शौचालयों की सफाई करना, चमड़ा रंगना, खाल उतारना सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 2012–13 में 12.66 लाख रुपये की राशि 565 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई।

(2) विभाग द्वारा चलाये जा रहे है पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को टाईप तथा शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2012–13 में 82.19 लाख रुपये की राशि 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई।

(3) वर्ष 2012–13 में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में स्थापित छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 13.83 लाख रुपये की राशि 28 छात्रों पर उनको होस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु खर्च की गई।

(4) हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले को वेतन तथा भत्ते देने के लिए 226.12 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012–13 में खर्च की गई ।

(5) उपरोक्त स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय, जिलों/तहसीलों आदि में नियुक्त अमले के वेतन तथा भत्तों पर वर्ष 2012–2013 में 1924.59 लाख रुपये की राशि (1906.74 लाख रुपये नान प्लान साईड पर और 17.85 लाख रुपये प्लान साईड) खर्च की गई।

3 यह प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा का वर्ष 2012–2013 की स्कीमों का वर्णन करती है । इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले पृष्ठों में भिन्न–भिन्न स्कीमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई स्कीमें शुरू की हैं परन्तु उन्हें दूसरे वर्गों के बराबर लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में विभाग इसके लिए और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा।

4. इस रिपोर्ट की समीक्षा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दी जाएं ।

कुमार सुनील गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 अप्रैल, 2015.

Review of the Annual Administrative Report of the Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana for the year 2012-2013.

The 1st June, 2015

No. 529-SW-(1)2015

During the year 2012–2013, a sum of Rs. 37025.55 lacs was allocated under State Plan (Rs. 14290.00 lacs), Centrally Sponsored Plan (Rs. 10785.20 lacs), Special Central Assistance (Rs. 1697.50 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 10252.85 lacs) for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department. During this period, against the above allocation, Rs. 33739.25 lacs were utilised under different schemes of State Plan (Rs. 13702.12 lacs), Centrally Sponsored Plan (Rs. 4141.75 lacs), Special Central Assistance (Rs. 1697.50 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 14197.88 lacs).

2. A summary of State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes is as under:-

A. STATE PLAN SCHEMES

(i) An amount of Rs. 2005.40 lacs was provided as financial assistance to 4254 beneficiaries under the "Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

(ii) An amount of Rs. 198.00 lacs was provided as financial assistance to 412 beneficiaries belonging to Tapriwas and Vimukt Jatis for construction of houses under the "Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

(iii) During this year, an amount of Rs. 100.00 lacs was provided as share capital to Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam and an amount Rs. 131.55 lacs was provided as administrative subsidy to bear administrative expenses.

(iv) An amount of Rs. 168.57 lacs was utilised for providing training to 2000 Scheduled Castes/Backward Classes trainees under the Scheme "Tailoring Training to Scheduled Castes/Backward Classes Widows/Destitute Women/ Girls ".

(v) Under the Scheme of "Indira Gandhi Priya Darshini Viwah Shagun Yojna", an amount of Rs. 8195.88 lacs was disbursed to 32676 beneficiaries during the year 2012-13.

(vi) During the year 2012-2013, a sum of Rs. 32.05 lac was spent on 880 Scheduled Castes and Backward Classes Students for providing them coaching for Civil Services & other higher services competitive/ entrance examinations from reputed private institutions.

(vii) An amount of Rs. 434.57 lacs was given as subsidy to bear administrative expenses to "Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation" during the year 2012-13.

(viii) An amount of Rs. 1799.70 lacs was disbursed to 22686 Students (18080 Scheduled Castes and 4606 Backward Classes) under "Dr. Ambedkar Medhavi Chhattra Yojna" during the year 2012-13.

(ix) Under the Scheme of Information Technology an amount of Rs. 23.65 lacs was utilised during the year 2012-13.

(x) An amount of Rs. 43.87 lacs was utilised for providing training to 180 youths under the Scheme of Up gradation of the Typing and Data Entry Skills of the SC/BC Unemployed youth through Computer's during the year 2012-13.

(xi) An amount of Rs. 2.86 lacs was disbursed to 32 SC girl students under the "Scheme of Anusuchit Jati Chhatra Uchch Shiksha Protsahan Yojna" during the year 2012-13.

(xii) An amount of Rs. 50.00 lacs was given to 28 SC/BC institutions/societies during the year 2012-13.

B. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

(i) An amount of Rs. 210.00 lacs was spent under the scheme, construction of three hostels for OBC boys/girls during the year 2012-2013.

(ii) An amount of Rs. 14467.84 lacs (Rs. 11251.72 lacs Non-Plan and Rs. 3216.12 lacs Central Share) was disbursed to 83377 Scheduled Castes Students under the Centrally Sponsored Schemes of "Post-Matric Scholarship for SC students" during the year 2012-13.

(iii) An amount of Rs. 510.51 lacs was disbursed as scholarship to 53191 Backward Classes students under the Scheme of "Post-Matric Scholarship Scheme for O.B.C students".

(iv) An amount of Rs. 16.95 lacs was spent on 64 students under "Up-gradation of merit of Scheduled Castes/Scheduled Tribes students" scheme during the year 2012-13.

(v) Schemes under Machinery for the Implementation of P.C.R. Act, 1955 and Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: -

(a) Legal Assistance :-

An amount of Rs. 3.48 lacs (Rs. 1.74 lacs Plan & 1.74 lacs Central Assistance) was disbursed to 64 persons under the "Legal Aid Scheme", during the year 2012-13.

(b) Incentive for Inter-Caste Marriage :-

Under this scheme, an amount of Rs. 105.50 lacs (Rs. 52.75 lacs State Plan and Rs. 52.75 lacs Central Assistance) was disbursed to 211 newly wedded couples as incentive.

(c) Award to Panchayats, Publicity of Schemes and Debates & Seminars for Removal of Untouchability :-

Under this scheme, an amount of Rs. 74.10 lacs (Rs. 37.05 lacs on State Plan side and Rs. 37.05 lacs from Central assistance) was utilised during this year. Out of this, an amount of Rs. 40.50 lacs (Rs. 20.25 lacs State Plan and Rs. 20.25 lacs Central Assistance) was given to 81 Panchayats for their outstanding work and Rs. 30.58 lacs (Rs. 15.29 lacs on State Plan and Rs. 15.29 lacs from Central Assistance) was spent on publicity of schemes and Rs. 3.02 lacs (Rs. 1.51 lacs from State Plan and Rs. 1.51 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on 48 Debates and Seminars.

(d) Monetary relief to the victims of atrocities under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

An amount of Rs. 193.26 lacs (Rs. 96.63 lacs State Plan and Rs. 96.63 lacs from Central Assistance) was paid to 212 persons under this Scheme.

C SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE SCHEME

Under the Special Central Assistance Scheme, a sum of Rs. 1197.50 lacs was given to Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the economic development of Scheduled Castes under various income generating schemes, Rs. 500 lakhs was provided to Haryana Renewable Energy Development Agency for the establishment of S.P.V. street lighting system in the villages having 50% or more Scheduled Castes population and Rs. 176.00 lacs were allocated to the Industrial Training Department for organizing special training for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and upgradation of I.T.I.s. which was drawn from their own account head, during the year 2012-2013.

Scheduled Castes Sub Plan (SCSP)

According to guidelines of the Government of India, Planning Commission, only those schemes are covered under SCSP, which ensure direct benefit to Scheduled Castes and priority should be given for providing basic minimum services like primary education, health, drinking water, nutrition, rural housing, rural link roads, rural electrification, agriculture and allied activities. As a part of national strategy, the villages having 40% and above Scheduled Castes population are being saturated first and provided with the infrastructure. The funds should be earmarked according to the proportion of SC population of the State population. During the year 2012-13, a sum of Rs. 2187.18 crore was spent under SCSP, out of the total State Plan expenditure Rs. 12520.87 crores i.e. expenditure is 17.47% by all departments concerned with SCSP.

D NON PLAN SCHEMES

(i) An amount of Rs. 12.66 lacs was disbursed as scholarship to 565 students under the Scheme of "Pre-Matric Scholarship to Children of those Parents who are engaged in Unclean Occupations i.e. scavenging of dry latrines, tanning and flaying" during the year 2012-13.

(ii) An amount of Rs. 82.19 lacs was utilised for providing training to 120 Scheduled Castes Students in Type and Shorthand in Pre-examination Training Centres during the year 2012-13.

(iii) During the year 2012-13 an amount of Rs. 13.83 lacs was utilised for 28 students for providing them hostel facilities in the Hostel for Denotified Tribes students in Jind.

(iv) An amount of Rs. 226.12 lacs was utilised to pay salaries and allowances to the staff of "Haryana Second Backward Classes Commission" during the year 2012-13.

(v) For the implementation of the aforesaid schemes, an amount of Rs. 1924.59 lacs (Rs. 1906.74 lacs Non Plan and Rs. 17.85 lacs Plan) was utilised during the year 2012-13 to pay salary and allowances to the staff posted at Head Quarter, Districts and Tehsil Level.

3. This Administrative Report describes the schemes of the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department for the year 2012-2013. The annexed report depicts the position in detail. While the State Govt. has initiated several schemes for socio-economic empowerment of Scheduled Castes & Backward Classes, persistent efforts are required to bring them at par with others. This Department will address it self to this task with greater determination in the coming year.

4. This Review of the Report may be published in the Haryana Government Gazette and its copies of the Report be sent to the Govt. of India and other concerned quarters.

KUMAR SUNIL GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Chandigarh :
The 6th April, 2015.

53367—C.S.—H.G.P., Chd.